

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *117
उत्तर देने की तारीख 11.02.2019
लघु उद्योग

*117. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री निशिकान्त दुबे:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अंतर्गत लघु उद्योगों की स्थापना के लिए कोई योजना लागू की है, ताकि उनकी विशेषकर देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 11.02.2019 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *117 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) सरकार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के माध्यम से खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआई) देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने तथा रोजगार सृजित करने के लिए 2008-09 से एक मुख्य ऋण सम्बद्ध सब्सिडी स्कीम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) स्कीम के अंतर्गत परियोजना की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र की इकाइयों के लिए 25.00 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत इकाइयों के लिए 10.00 लाख रुपए है। इस स्कीम के अंतर्गत महिला उद्यमियों को विशेष श्रेणी के अंतर्गत किया जाता है तथा वे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित परियोजना के लिए क्रमशः 25% और 35% सब्सिडी के पात्र हैं। महिला लाभार्थियों के लिए अपना अंशदान परियोजना लागत का केवल 5% है जबकि सामान्य श्रेणी के लिए यह 10% है। पीएमईजीपी के अंतर्गत स्थापित कुल परियोजनाओं में से लगभग 30% परियोजनाएं महिलाओं द्वारा स्थापित की गई हैं। महिलाओं द्वारा स्थापित अब तक परियोजनाओं का राज्यवार ब्योरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ग) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, केवीआईसी के माध्यम से देश में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोग ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में सुधार करने के लिए सहित निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है।

1) खादी कार्यक्रम : खादी कार्यक्रम के विकास और संवर्धन के लिए केवीआईसी 34 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी) की सहायता से निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित करता है। और 2518 खादी संस्था 4.65 लाख व्यक्तियों (संचयी) को रोजगार प्रदान कर रही हैं जिनमें से 80 प्रतिशत से अधिक महिला कारीगर हैं। खादी कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी का हिस्सा अनुबंध-II में दिया गया है:

- i) बाजार संवर्धन और विकास सहायता (एमपीडीए)
- ii) ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आईसेक)
- iii) आम आदमी बीमा योजना (पूर्ववर्ती जनश्री बीमा योजना)
- iv) कारीगर कल्याण निधि ट्रस्ट (एडब्ल्यूएफटी)
- v) खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम
- vi) विद्यमान कमजोर खादी संस्थानों की अवसंरचना का सुदृढीकरण और विपणन अवसंरचना के लिए सहायता।

2) ग्रामोद्योग कार्यक्रम: कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ सात समूहों में विस्तृत रूप से वर्गीकृत किया गया है जो निम्नानुसार हैं:-

- i) कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एबीएफपीआई)
- ii) वन आधारित उद्योग (एफबीआई)
- iii) हस्तनिर्मित कागज और फाईबर उद्योग (एचएमपीएफआई)
- iv) खनिज आधारित उद्योग (एमबीआई)
- v) पॉलीमर और कैमिकल आधारित उद्योग (पीसीबीआई)
- vi) ग्रामीण इंजीनियरिंग और बायो प्रोद्योगिकि उद्योग (आरईबीटी)
- vii) सेवा एवं वस्त्र उद्योग

3) ग्रामीण भारत में महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मंत्रालय द्वारा मिशन सोलर चरखा का शुभारंभ किया गया है। इस स्कीम में केन्द्रित ग्रामों में सोलर चरखा स्थापित करने का प्रावधान है जिससे 8 से 10 किलोमीटर के दायरे के गांवों के कारीगर सोलर चरखाओं के फैब्रिक के उत्पादन और प्रशिक्षण के माध्यम से लाभान्वित हो सकते हैं।

4) खादी सुधार और विकास कार्यक्रम (केआरडीपी) का उद्देश्य खादी की सतत, कतिनों (स्पिनरों) एवं बुनकरों के लिए वर्धित आय और रोजगार, कारीगरों के कल्याण में वृद्धि के साथ खादी क्षेत्र को पुनरुद्धार करना तथा ग्रामोद्योग के साथ सहयोगात्मकता (सिनर्जी) प्राप्त करना है। खादी सुधार पैकेज में निम्नलिखित क्षेत्रों (i) कारीगरों की आय एवं सशक्तिकरण (ii) 400 खादी संस्थाओं को प्रत्यक्ष सुधार सहायता तथा (iii) वेल निट (Well knit) एमआईएस के कार्यान्वयन में सहायता सुधार पर विचार किया गया है।

5) परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति) परंपरागत उद्योगों एवं कारीगरों को क्लस्टरों में संगठित कर परंपरागत उद्योगों को अधिक उत्पादक एवं प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए 2005-06 से शुरू की गई है। इस स्कीम में उत्पादन उपकरणों को बदलने, सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) की स्थापना, उत्पादन विकास, गुणवत्ता सुधार, उन्नत विपणन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण इत्यादि के लिए आवश्यकता आधारित सहायता प्रदान करने की परिकल्पना है। स्कीम को 2016-17 के दौरान पुनरुद्धारित स्कीम के रूप में संशोधित किया गया।

6) क्षमता निर्माण (सीबी):- केवीआईसी 40 विभागीय और गैर विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है। ये प्रशिक्षण केन्द्र विभिन्न विषयों नामतः साबुन और डिटरजेंट बनाना, खाद्य मर्दों, बेकरी उत्पादों, रेडीमेड वस्त्रों, मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती बनाने, मोमबत्ती बनाने, मोटर बाईडिंग इत्यादि में आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण प्रदान करता है।

7) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी:- शिल्पकारों के उपकरणों और विनिर्माण तकनीकी में सुधार करके उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) महत्वपूर्ण इनपुट सामग्री है। केवीआईसी में कारीगरों की आय और उत्पादकता बढ़ाने और उनके कार्यों में नीरसता को कम करके उत्पादन प्रक्रिया को अधिक कारीगर अनुकूल बनाना जारी रखा है। केवीआईसी की अनुसंधान एवं विकास स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न उन्नत प्रौद्योगिकियों को विकसित किया गया है जो ग्रामीण उद्योग क्षेत्र द्वारा विनिर्मित उत्पादों की गुणवत्ता, उत्पादकता और पैकेजिंग में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाती हैं।

अनुबंध-1

दिनांक 11.02.2019 के लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *117 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-1 वर्ष 2008-09 से 2018-19 (23.01.2019 तक) प्रारंभ से पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित परियोजनाओं की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएमईजीपी के अंतर्गत महिला उद्यमी
1	जम्मू और कश्मीर	6586
2	हिमाचल प्रदेश	2542
3	पंजाब	3182
4	चंडीगढ़	132
5	हरियाणा	2234
6	दिल्ली	413
7	राजस्थान	3887
8	उत्तराखंड	2767
9	उत्तर प्रदेश	12790
10	छत्तीसगढ़	3252
11	मध्य प्रदेश	5280
12	सिक्किम	196
13	अरुणाचल प्रदेश	788
14	नागालैंड	2019
15	मणिपुर	1912
16	मिजोरम	2321
17	त्रिपुरा	2053
18	मेघालय	1269
19	असम	10738
20	बिहार	5264
21	पश्चिम बंगाल	11496
22	झारखंड	2525
23	ओडिशा	6846
24	अंडमान निकोबार और द्वीप समूह	348
25	गुजरात	5941
26	महाराष्ट्र	9685
27	गोवा	326
28	आंध्र प्रदेश	6933
29	तेलंगाना	1342
30	कर्नाटक	5302
31	लक्षद्वीप	45
32	केरल	6066
33	तमिलनाडु	11732
34	पुदुचेरी	304
	कुल	138516

दिनांक 11.02.2019 के लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *117 के भाग(ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II
वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान वितरित की गई मार्जिन मनी (एमएम) और महिला उद्यमियों द्वारा
स्थापित परियोजनाओं की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17		2017-18	
		स्थापित परियोजनाओं की संख्या	वितरित की गई मार्जिन मनी सब्सिडी (लाख रु. में)	स्थापित परियोजनाओं की संख्या	वितरित की गई मार्जिन मनी सब्सिडी (लाख रु. में)
1	जम्मू और कश्मीर	476	634.15	1188	1718.41
2	हिमाचल प्रदेश	198	422.73	303	765.23
3	पंजाब	454	1316.11	580	1861.72
4	चंडीगढ़	14	25.07	18	32.58
5	हरियाणा	283	662.57	422	958.11
6	दिल्ली	40	58.51	43	57.16
7	राजस्थान	314	1250.10	337	1332.04
8	उत्तराखंड	296	528.92	327	676.04
9	उत्तर प्रदेश	1387	5030.05	1492	5417.78
10	छत्तीसगढ़	319	977.37	327	959.80
11	मध्य प्रदेश	512	2100.23	518	2645.46
12	सिक्किम	11	11.16	15	19.35
13	अरुणाचल प्रदेश	104	138.50	86	121.22
14	नागालैंड	334	626.72	427	1178.34
15	मणिपुर	223	581.75	237	473.38
16	मिजोरम	128	217.30	134	133.83
17	त्रिपुरा	452	734.81	261	393.52
18	मेघालय	142	155.15	31	56.98
19	असम	1484	1015.53	581	528.41
20	बिहार	915	2115.84	647	1778.56
21	पश्चिम बंगाल	802	1535.21	406	1144.53
22	झारखंड	292	494.67	215	537.20
23	ओडिशा	942	2144.02	777	2095.83
24	अंडमान निकोबार और द्वीप समूह	22	15.33	38	33.02
25	गुजरात	567	3905.07	1017	7785.33
26	महाराष्ट्र	783	2233.86	1079	3153.11
27	गोवा	37	95.36	19	43.08
28	आंध्र प्रदेश	294	2631.29	719	2761.31
29	तेलंगाना	218	812.76	370	1534.84
30	कर्नाटक	816	2362.30	580	1853.93
31	केरल	635	1112.50	525	960.76
32	तमिलनाडु	1248	2955.01	1929	3314.02
33	पुदुचेरी	26	49.20	21	30.98
	कुल	14768	38949.15	15669	46355.86